संपूर्ण स्वच्छता अभियान

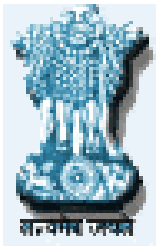

सत्यमेव जयते

डॉ0 रघुवंश प्रसाद सिंह

ग्रामीण विकास मंत्री

भारत सरकार

का अभिभाषण

राज्य स्तरीय सम्मेलन

बड़ौदा, गुजरात

6, अगस्त, 2004

संपूर्ण स्वच्छता अभियान, राज्य स्तरीय सम्मेलन, बड़ोदरा (गुजरात)
6 अगस्त, 2004

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी का अभिभाषण

गुजरात राज्य में सम्पूर्ण स्व्च्छता अभियान के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है । गुजरात सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है । इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं गुजरात सरकार के पंचायत मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चुदासमा एवं उनके अधिकारियों को बधाई देता हूं ।

महात्मा गांधी जी ने कहा था 'स्वच्छता में ही देवत्व है' । जहां स्वच्छता रहती है वहीं समृद्धि भी रहती है । हर व्यक्ति अपने आस-पास का वातावरण स्वच्छ देखना चाहता है । यह मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है । परन्तु दुख का विषय यह है कि हांलाकि हम सब व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति सचेतन रहते है किन्तु अपने आस-पास के वातावरण की स्वच्छता के प्रति सजग नहीं रहते । यह बहुत दुर्भागयपूर्ण है कि स्वच्छता के अभाव के चलते आज भी हमारे देश में चार से पाँच लाख बच्चे प्रतिवर्ष डायरिया, आंत्रशोध, जैसी बीमारियों की भेंट चढ़ जाते हैं । लाखों गरीब लोग इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है, एवं काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

यह अत्यन्त ही दुर्भाग्य का विषय है कि आजादी के 57 वर्षों के बाद भी हमारे गॉवों में सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है । ज्यादतर लोग खुले में शौच करते हैं जिससे गंदगी एवं बीमारी फैलती है । खुले में त्याग किया हुआ मल हमारे जल स्त्रोत में मिलकर उसे दूषित करता है । 2001 की जनगणना के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 22% घरों में शौचालय की व्यवस्था थी । देश की आबादी का 65% भाग खुले में शौच करता है एवं बीमारी को दावत देता है । यह लोगों की काफी प्राचीन एवं परंपरागत आदत है जिसे बदलना बहुत जरूरी है। आज देश में सिर्फ 26% जनता गरीबी की रेखा के नीचे वास करती है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में 78% लोगों के घरों में शौचालय नहीं है । यह इस बात का द्योतक है कि यह समस्या सिर्फ गरीब परिवारों के लिए ही नहीं है । जो साधन संपन्न हैं वह भी खुले में शौच करने की प्रथा को चला रहे हैं । गुजरात राज्य भी इससे अछुता नहीं है । गुजरात ने आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है एवं आर्थिक मानदण्डो को यदि देखा जाए तो यह देश के अग्रणी राज्यों में है । फिर भी गुजरात की 78% ग्रामीण जनता खुले में शौच करती है । यह विषय गम्भीर है एवं इस पर गहन चिंतन की जरूरत है ।

गॉवों में स्वच्छता की सुविधा को बढ़ाना हमारी सरकार के **राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम** का महत्वपूर्ण हिस्सा है । हमारी केन्द्र सरकार यह चाहती है कि गॉव में स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ाया जाए एवं हर घर, विद्यालय, आंगनवाड़ी एवं सामुदायिक जगहों पर शौचालय बनवाए जाएं । लागों की मानसिकता को बदला जाए एवं उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए । हम चाहते हैं कि 2012 तक इस देश के किसी भी कौने में कोई भी खुले में

शौच न करें । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम देश के प्रत्येक जिले में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाना चाहते हैं । इस अभियान के द्वारा हमें हर व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा । इस अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए यह जरूरी है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें एक साथ मिलकर काम करें । यह कार्यक्रम महज सरकारी कार्यक्रम न रह जाए, इस हेतु लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पदक्षेप लिए गए हैं । इतने बड़े स्तर का अभियान, जिसमें हमें आधी से ज्यादा आबादी तक पहुंचना है, उसका सफल कार्यान्वयन लोगों एवं पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित किए बगैर असंभव है । सरकारी कर्मचारियों, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठन एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को मिलकर इस कुरीति से संघर्ष करना पड़ेगा ।

मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में सरपंचों को बुलाया गया है । मुझे विश्वास है कि इस प्रदर्शनी को देखने के बाद अपने-अपने गॉवों में स्वच्छता की सुविधा को बढ़ाने के लिए उनका उत्साह बढ़ेगा । वे इस समस्या से भली-भांति अवगत होकर नए जोश के साथ अपने क्षेत्रों में जाएंगे । मैं आवाहन करता हूं कि वे शपथ लें कि अलगे 12 महीनों के अंदर अपने ग्राम को स्वच्छ व निर्मल बनाएंगे । उनकी सक्रिय भागीदारी से ही स्वच्छता अभियान सफल होगा ।

लोगों को इस अभियान के प्रति उत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने **निर्मल ग्राम पुरस्कार** की घोषणा की है जो उन सभी पंचायती राज संस्थाओं को मिल सकता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्रत्येक घरों में शौचालय बनवा दिए हों एवं लोग खुले में शौच नहीं करते । पंचायती राज संस्था, गैर-सरकारी संगठन अथवा सरकारी विभाग के वे प्रतिनिधि जिन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है उन्हें भी पुरस्कृत करने का प्रावधान है । हम चाहते हैं कि इस अभियान में निष्ठापूर्वक जुड़े हुए हर व्यक्ति को सम्मान एवं आदर मिले ।

हमारे मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग ने देश के 398 जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की स्वीकृति दे दी है । इसमें गुजरात राज्य के भी 5 जिले हैं। इसके अलावा 130 जिलों में भी इस कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी है । गुजरात के भी बचे हुए 20 जिले इसमें शामिल हैं । विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलने के बाद हमारा विभाग उस पर यथोचित कार्यवाही करेगा । इस कार्यक्रम को चलाने हेतु हर संभव सहायता सभी राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी ।

अभी तक अनुमोदित 398 जिलों के प्रोजेक्टों की कुल लागत 3750 करोड़ रुपए (तीन हजार सात सौ पचास करोड़ रुपए) है । जिसमें केन्द्र सरकार की राशि 2,220 करोड़ रुपए (दो हजार दो सौ बीस करोड़ रुपए), राज्य सरकार की 847 करोड़ रुपए (आठ सौ सतालीस करोड रुपए) है एवं लोगों की भागीदारी 704 करोड़ रुपए (सात सौ चार करोड़ रुपए) की होगी । केन्द्र सरकार को अपनी राशि इन प्रोजेक्टों को देने में कोई असुविधा न हो इस हेतु हम

सचेतन हैं । हमारी सरकार ने स्वच्छता कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष की तुलना में ढाई गुणा राशि उपलब्ध करवाई है एवं अगर जरूरत पड़ी तो और भी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी । कई राज्य सरकारों को जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अपने हिस्से की राशि उपलब्ध करवाने में असुविधा हो रही है । उन राज्यों की स्थिति को समझते हुए हमने 12वें वित्त आयोग के सामने प्रस्ताव रखा है कि राज्य सरकारों को स्वच्छता कार्यक्रम हेतु विशेष अनुदान दिया जाए । मुझे विश्वास है कि वित्त आयोग विषय की गम्भीरता को समझते हुए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध करवाएगा ।

देश के इतिहास में गुजरात का एक विशेष स्थान है । गुजरात की धरती पर महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे राष्ट्र नेता जन्में हैं जिन्हों देश को नई दिशा दी है । महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ स्वच्छता अभियान एवं हरिजन मुक्ति आंदोलन को चलाया था । जिस राज्य की ऐसी विरासत हो वहां पर स्वच्छता अभियान तो निश्चित रूप से सफल होना चाहिए ।

मुझे बताया गया है कि गुजरात के कुछ जिलों में **राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, दुग्ध उत्पादक संध एवं यूनिसेफ** की सहायता से अनोखा कार्यक्रम चलाया जा रहा है । जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादक संघ के सदस्यों को शौचालय बनवाने हेतु शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसे मासिक किस्तों में ग्रामीण किसान चुका रहे हैं । इससे दूध की उत्पादकता भी बढ़ रही है एवं गॉवों में साफ-सफाई भी बढ़ रही है । यह प्रयोग निश्चित तौर से एक अच्छा प्रयोग है।

इसे राज्य के सभी क्षेत्रों में लागू करने की संभावनाओं पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए । अगर यह प्रयोग सफल होता है तो देश के अन्य राज्यों में भी चलाया जा सकता है । इस हेतु अगर जरूरत पड़ी तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के दिशा-निर्देशों में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं ।

यदि हमारे गॉवों को समृद्ध होना है तो गॉवों को स्वच्छ भी होना होगा । हमारी माताओं एवं बहनों को असुविधा न हो इस हेतु हर घर में शौचालय बनना चाहिए । जल निकासी की सुविधा के लिए सोखते गड्डे बनने चाहिएं । अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु लोगों की मानसिकता को बदलना होगा । इसके लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की जरूरत है । मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने राज्य व्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है । मुझे विश्वास है कि आप इस अभियान में सफल होंगे एवं हम सबका सहयोग आपके साथ होगा ।

इस अभियान की शुरूआत आपने जिस जोरदार तरीके से की है उससे मैं कार्यक्रम की सफलता के प्रति आशावान हूं । आज जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो काफी ज्ञानवर्द्धक है एवं इस विषय-वस्तु की सही जानकारी देती है । हमारे पेयजल आपूर्ति विभाग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे स्वच्छता कार्यक्रम पर एक सीडी बनवाई है । मैं अपने संयुक्त सचिव महोदय से आवेदन करूंगा कि उसे भी इस प्रदर्शनी में दिखाया जाए ताकि लोग उसका लाभ उठा सके इसके अलावा विभाग द्वारा प्रकाशित की गई विभिन्न पुस्तिकाओं को भी इस प्रदर्शनी में रखा जाए ।

मैं एक बार फिर से इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए आप सबको बधाई देता हूं ।

धन्यवाद ।

जयहिन्द ।